(3) The Scientific Research Institutions set up by Industry are recognised as Research Institutions under Clause 35 (i) (ii) of the Income-Tax Act which provides that the donations received by the Research Institutions are deducted from the taxable income of the donors. Also the income of the Research Institutions recognised under this clause is also exempted from income-tax under clause 10 (21) of the Act.

(4) In order to promote scientific research the rate of development rebate on machinery and plant installed for scientific research was enhanced from the general rate of 20% to the priority rate of 55%. with effect from 1967-68 Also the whole of the capital expenditure incurred after 31st March, 1967 on assets used for scientific research is allowed as a deduction in the year it is incurred

(5) To supplement the efforts of the industry, the Government have set up various Institutes and Design Centres, for example, the Central Machine Tools Institute Bangalore and the Foundry Forge Institute, Ranchi, for training and research.

Examination of Rate of Railway's Contribution to Central Revenues

1264. SHRI S. S. KOTHARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rate of Railway's contribution to the Central Revenues is being re-examined;

(b) if so, what is the result of such scrutiny; and

(c) whether Government are in favour of an increase in the rate of such contribution ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The rate of dividend payable by the Railways and other ancillary matters are under review by the Railway Convention Committee, 1968.

(b) The review is still to be completed.

(c) Does not arise.

लघु उद्योगों को लाइसेंस और ऋण देने के बारे में लोकनायन समिति की सिफारिश

1265. श्री शिवकुमार शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक नाथन समिति ने सिफारिश की है कि लघु उद्योगों के सम्बन्ध में लाइसेंस पद्धति को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और इन उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पर्याप्त ऋण दिये जाने चाहिये ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं । इस समय लघु उद्योगों को लाइसेंस प्रदान करने की कोई पद्धति प्रचलित नहीं है । लोकनाथन समिति ने राष्ट्रीयकृत बंकों द्वारा अग्रिम ऋण दिये जाने के विषय में कोई विशेष सिफारिश नहीं किया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बोकारो इस्पात कारखाने तथा हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन के लिये रूस को सहायता

1266. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण में और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये आर्थिक सहयोग देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर काम कर रहे कुछ भारतीय इंजीनियरों के अधिक उज्जवल भविष्य के लिये कुछ विशेष उपाय सुझाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो रूस से किस प्रकार का सहयोग मिलने की सम्भावना है; और यह सहयोग कब तक प्राप्त होगा और इससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). **बोकारो इस्पात कारखाना** : यह निश्चय हुआ है कि भारत और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकारें बोकारो इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 40 लाख टन तक बढ़ाने में सहयोग देंगी। सोवियत सरकार सोवियत संघ से प्राप्त किये जाने वाले उपकरणों और सेवाओं के खर्च की पूर्ति के लिए ऋण देगी। सम्बन्धित सोवियत संगठन भारतीय संगठनों की सहायता करेंगे जिससे इस्पात कारखाना यथाशीघ्र निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सके।

भारी इंजीनियरी निगम : यह निश्चय किया गया है कि भारी इंजीनियरी निगम के भारी मशीनें बनाने वाले कारखाने की, जो सोवियत सहयोग से स्थापित किया गया है, क्षमता का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के कुछ विशेष प्रकार के उत्पादनों के निर्माण के लिये सोवियत संघ के सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा जिनका दीर्घकाल तक सोवियत संघ को निर्यात किया जा सके। ब्योरों के बारे में निर्णय करने हेतु दिल्ली में विशेषज्ञों द्वारा आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

Reservation in Mithila Express

1267. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the statement laid on the Table on the 24th December, 1969 in implementation of the assurance arising out of the reply given to Unstarred Question No. 2608 on the 11th March, 1969 regarding reservation in Mithila Express and state :

(a) where was the passenger contacted and by which Railway officials and on what date ;

(b) were those contacting officials duly authorised by the Railway authorities to do so;

(c) did those officials pressurize the passenger to give in writing about the situation;

(d) if they did, were they authorized by the Railway authorities to do so; and

(e) if they were not so authorized, the reasons for those officials asking the passenger to give in writing about the situation ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA) : (a) The passenger was contacted at his residence, Village Malangia (Madhubani) by an Inspector of the North Eastern Railway on 31st July, 1969.

(b) Yes.

(c) No.

(d) and (e). Do not arise.

Industrial Development of North Bihar

1268. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of the Reserve Bank of India has been entrusted with the task of making a survey of North Bihar and to make recommendations for its industrial development;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the specific plans for the industrial development of North Bihar during the Fourth Plan period ?